



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2001/श्रावण 29, 1923

No. 223]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2001/SRAVANA 29, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2001

विषय: कोरिया गणराज्य और तुर्की से पार्शियली ओरिएण्टेड यार्न (पी ओ वाई) के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच शुरु करना ।

सं. 36/1/2001-डीजीएडी.—पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को कोरिया गणराज्य और तुर्की से आयातित पार्शियली ओरिएण्टेड यार्न (पी ओ वाई) के कथित पाटन के खिलाफ पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए याचिका प्राप्त हुई है । मैसर्स एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री 125 उदय पार्क, प्रथम तल नई दिल्ली-110049 ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें कोरिया गणराज्य और तुर्की (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) से पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

2. घरेलू उद्योग

यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है। जिन कंपनियों ने प्रस्तावित जांच में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है, वे हैं- मैसर्स सेंचुरी एंका लि., मैसर्स इण्डो रामा सिंथेटिक्स (आई) लि., मैसर्स रिलायस इंडस्ट्रीज लि., और निम्नलिखित कंपनियां अर्थात् मैसर्स डी सी एल पालिस्टर्स लि., मैसर्स संघी पालिस्टर्स लि., मैसर्स रेक्रोन सिंथेटिक्स लि., वर्तमान याचिका का समर्थन कर रही हैं। जांच अवधि के दौरान भागीदार और समर्थक कंपनियों का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 65% बनता है। इसलिए इनके पास घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का आधार है।

3. शामिल उत्पाद:

याचिका में शामिल उत्पाद कोरिया गणराज्य और तुर्की के मूल का अथवा वहां से निर्यातित पार्शियली ओरिएण्टेड यार्न(पी ओ वाई) है। उत्पाद एच एस वर्गीकरण के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 54.02 और भारतीय टैरिफ वर्गीकरण के तहत 5402.33 के अंतर्गत वर्गीकृत है। उन्होंने यह भी कहा है कि 5402.33 के तहत वर्गीकृत पी एफ वाई और 5402.43 के तहत वर्गीकृत प्लैट यार्न और पालिस्टर के अन्य विभिन्न यार्न भी शीर्ष 5402.42 के तहत गलत ढंग से वर्गीकृत है जबकि यह शीर्ष पालिस्टर के पार्शियली ओरिएण्टेड यार्न के लिए उद्दिष्ट है। तथापि यह वर्गीकृत मात्र संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

4. शामिल देश:

वर्तमान जांच में शामिल देश कोरिया गणराज्य और तुर्की (संबद्ध देश) हैं

5. समान वस्तु:

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित माल/संबद्ध देशों में उत्पादित/उनके मूल के या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तुएं हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित माल को नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित माल के समान वस्तुएं माना जा रहा है।

6. सामान्य मूल्य:

याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि दिनांक 31 मई 2001 की अधिसूचना सं.28/2000-एन टी के अनुसार कोरिया गणराज्य और तुर्की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। याचिकाकर्त्ताओं ने अनुरोध किया है कि भारत को एक प्रतिनिधि देश माना जाय और भारत में घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तु के उत्पादन की पारिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य को स्वीकार किया जाए जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और समुचित लाभ मार्जिन का विधिवत समायोजन किया गया हो।

7. निर्यात कीमत:

याचिकाकर्त्ताओं ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) की नवीनतम उपलब्ध सूचना और गौण स्रोत (मैसर्स मिटकान लि.) से प्राप्त खेपवार आयात सूचना के अनुसार निर्यात कीमत प्रस्तुत की है। इस प्रकार भारत में संबद्ध देशों से निर्यात की प्रचलित कीमत के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

8. पाटन मार्जिन:

इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से भारत को किए गए निर्यात की कीमत उक्त देशों में सामान्य मूल्य से कम थी। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद का कोरिया गणराज्य और तुर्की से भारत में पाटन किया जा रहा है।

9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध:

घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाली क्षति से संबंधित विभिन्न मापदंड जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, आयातों का बाजार हिस्सा, उनकी मात्रा, घरेलू उद्योग में बिक्रियों की मात्रा, लाभ प्रदता, कीमतों में कटौती इत्यादि संचयी एवं सामूहिक रूप से प्रथम दृष्टया यह संकेत देते हैं कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

10. पाटनरोधी जांच शुरू करना:

अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी कोरिया गणराज्य और तुर्की के मूल अथवा वहां से निर्यातित पार्शियली ओरिएण्टेड यार्न (पी ओ वाई) के आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं ।

11. जांच अवधि:

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक (12 महीने) की है ।

12. सूचना देना:

संबद्ध देशों में जिन निर्यातकों और भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे श्री एल.वी.सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विभाग वाणिज्य, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं ।

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

13. समय सीमा:

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी इस प्रकार निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति के बाद उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

15. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जाँच में बाधा डालती है अथवा उक्त सूचना किसी भी रूप में अधूरी पायी जाती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

एल.वी. सप्तश्रुति, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2001

Subject:- Initiation of Anti-dumping investigations concerning imports of Partially Oriented Yarn (POY) from Republic of Korea and Turkey.

F. No. 36/1/2001-DGAD.— The Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties has received a petition for initiation of anti-dumping investigations against alleged dumping of Partially Oriented Yarn of Polyester(POY) imported from Republic of Korea and Turkey. M/s. Association of Synthetic Fibre Industry, 125 Uday Park, 1st Floor, New Delhi-110 049 have filed a petition in accordance with Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Partially Oriented Yarn from Republic of Korea and Turkey (also hereinafter referred to as subject countries) and requested for initiation of anti-dumping investigation and levy of anti-dumping duty.

2. **Domestic Industry:-** The petition has been filed by M/s. Association of Synthetic Fibre Industry, New Delhi on behalf of the domestic industry. The companies that have conveyed their willingness to participate in the proposed investigations are M/s Century Enka Ltd., M/s Indo Rama Synthetics(I) Ltd., M/s Reliance Industries, Ltd., and following companies are supporting the present petition viz M/s DCL Polyesters Ltd., M/s Sanghi Polyesters Ltd., M/s Recron Synthetics Ltd.. The share of participating and supporting companies account to about 65% of total Indian production during the period of investigation and therefore, have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry.

3. Product Involved:- The product involved in the petition is Partially Oriented Yarn of Polyester (POY) (also hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Republic of Korea and Turkey. The product is classified under Customs Tariff Heading 54.02 under HS Classification and 5402.42 under Indian Customs Tariff Classification. The Petitioners have also stated that PFY classified under 5402.33 and Flat yarns classified under 5402.43 and other variants of yarns of polyester are also misclassified under the heading 5402.42 meant for 'Partially Oriented Yarns of Polyesters (POY)'. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the present investigation.

4. Country Involved:- The countries involved in the present investigation are Republic of Korea and Turkey (subject countries).

5. Like Article:- The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods produced /originating in or exported from the subject countries. Goods produced by petitioners are treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

6. Normal Value: The petitioner has claimed that they have not been able to get an accurate and adequate evidence with regard to domestic price in respect of POY in the subject countries. In the circumstances they have claimed the normal value based on the constructed cost of production on the basis of PET – CHAIN Strategic Analysis (1996-2006 OF Dweitt & Co., Incorporated) duly adjusted to include selling general and administrative expanses and the reasonable profit margin.

7. Export Price:- The petitioners have provided the import data as per Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) latest available and have requested the Authority not to rely on the same, due to inclusion of misclassified imports of POY and other yarns which are not subject

goods. They have claimed export price on the basis of data compiled by MITCON Ltd , giving consignment-wise import information. There is sufficient prime facie evidence with regard to the export price of the subject goods from the subject countries.

8. Dumping Margin: There is sufficient prime facie evidence that export prices to India from subject countries were lower than the normal values in the said countries. Thus, there is sufficient evidence that the product under consideration is being dumped into India from Republic of Korea and Turkey .

9. Injury and Causal Link : The various parameters relating to injury affecting domestic industry such as production, capacity utilisation, market share, volume of imports, volume of sales of domestic industry, profitability, price undercutting etc. collectively and cumulatively, indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping.

10. Initiation of Anti Dumping Investigation: The Designated Authority, therefore, initiates anti dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of POY originating in or exported from Republic of Korea and Turkey.

11. Period of Investigation: The period of investigation for the purposes of present investigation is 1st April,2000 to 31st March, 2001 (12 months).

12. Submission of Information: The exporters in the subject countries and importers in India known to be concerned are being addressed to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make known their views to **Shri L.V.Saptharishi, Designated Authority and Additional Secretary to Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.** Any other interested party

may also make its submission relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

13. Time Limit:- Any information relating to the present investigation may be sent in writing so as to reach the Designated Authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately.

14. Inspection of Public File:- In terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by the other interested parties after the expiry of time limit thus set out.

15. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation or the information is incomplete in any respect, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority